पीएम विश्वकर्मा योजना से मजदूर सशक्त

30 लाख कारीगरों का पंजीकरण | **41** हजार करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत | **618** जिलों में 497 प्रबंधन इकाइयां

नई दिल्ली, 17 सितंबर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है. सरकारी आंकड़ों के अनुसार, योजना के तहत 30 लाख से अधिक कारीगरों और शिल्पकारों ने पंजीकरण कराया है, जबकि 41,188 करोड़ रुपये के 4.7 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं.

प्रमुख उपलब्धियाँ और लक्षित समूह- सरकार द्वारा जारी जानकारी के अनुसार, लगभग 26 लाख कारीगरों ने

अपना कौशल सत्यापन पूरा कर लिया है, जिनमें से 86% ने अपनी बेसिक ट्रेनिंग भी पूरी कर ली है. इस योजना में राजमिस्त्री सबसे अधिक पंजीकृत व्यवसाय है.

टूलकिट प्रोत्साहन- कारीगरों को आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए 23 लाख से अधिक ई-वाउचर जारी किए गए हैं.

योजना का उद्देश्य- 17 सितंबर 2023 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य कारीगरों और शिल्पकारों के कौशल को बढ़ाना और उनके उत्पादों की पहुंच को व्यापक बनाना है. इस पर 13,000 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है, जो 2027-28 तक चलेगा.

समावेशी विकास- यह योजना विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण और हाशिए पर

योजना का क्रियान्वयन और भविष्य की योजना

योजना को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए, देश के 618 जिलों को कवर करते हुए 497 जिला परियोजना प्रबंधन इकाइयां नियुक्त की गई हैं. इन इकाइयों का मुख्य कार्य कारीगरों में जागरूकता बढ़ाना, प्रशिक्षण की जानकारी देना और प्रशिक्षण केंद्रों की निगरानी करना है. मंत्रालयों और डीपीएमयू के सहयोग से, यह योजना कारीगरों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता देने, कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और बिना गारंटी वाले ऋण तक पहुंच प्रदान करने पर केंद्रित है. इसके अलावा, यह डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने और कारीगरों को ब्रांड प्रचार तथा वैश्विक बाजारों से जोड़ने पर भी ध्यान देती है. इस पहल से सदियों पुरानी पारंपरिक कलाओं को आधुनिक दुनिया में संरक्षित और प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे छोटे कारीगरों को पहचान और सशक्तिकरण मिल रहा है.

सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर

भोपाल, 17 सितंबर. त्योहारी सीजन, सांस्कृतिक मांग और जीएसटी सुधारों के कारण भारत में सोने के आभूषणों की मांग बढ़ने की उम्मीद है, भले ही कीमतें पहले ही रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुकी हों. यह बात मिराए एसेट म्यूचुअल फंड की एक रिपोर्ट में सामने आई है.

रिपोर्ट के अनुसार, भारत और चीन सोने के आभूषणों की वैश्विक मांग में 50 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं. चीन में उपभोक्ता खर्च में सुधार भी शहरी आभूषण खरीदारी को बढ़ा सकता है.विश्व स्वर्ण परिषद की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतें अगस्त 2025 में 3,429 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुई, जो मासिक आधार पर 3.9% की वृद्धि दर्शाती हैं. 2025 में अब तक सोने में 31% की वृद्धि देखी गई है.

भारत का अमेरिका को निर्यात अगस्त में 16 प्रतिशत गिरा

मई में 8.8 अरब डॉलर से घटकर अगस्त में 8.0 अरब डॉलर

परिधान, रत्न-जवाहरात, चमड़ा, झींगा और कालीन उद्योग प्रभावित

नई दिल्ली17 सितंबर. भारत का अमेरिका को निर्यात लगातार तीसरे महीने गिरा है, जिसका मुख्य कारण वाशिंगटन द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ हैं. ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव (त्रञ्जऋ्छ) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अगस्त 2025 में निर्यात में 16.3% की तेज गिरावट दर्ज की गई, जो इस वर्ष की सबसे बड़ी मासिक गिरावट है. यह गिरावट 7 अगस्त को टैरिफ 10% से बढ़कर 25% और फिर 27 अगस्त को 50% होने के बाद देखी गई.

मई में 4.8% की वृद्धि के साथ निर्यात 8.8 अरब डॉलर तक पहुँचने के बाद, जून में 5.7% की गिरावट के साथ यह 8.3 अरब डॉलर पर आ गया. जुलाई में भी यह सिलसिला जारी रहा और निर्यात 3.6% घटकर 8.0 अरब डॉलर हो गया. अगस्त में 16.3% की भारी गिरावट ने निर्यातकों पर गंभीर दबाव डाला है.

रिपोर्ट में बताया गया है कि टैरिफ में बढ़ोतरी और निर्यात में गिरावट में सीधा संबंध है. अप्रैल तक भारतीय सामान सामान्य शुल्क पर अमेरिका में प्रवेश करते थे. अप्रैल में 10% का यूनिवर्सल टैरिफ लगने के बाद भी मई तक इसका खास असर नहीं दिखा क्योंकि खरीदारों ने पहले ही खरीदारी कर ली थी. लेकिन जून से नए शुल्क भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को प्रभावित करने लगे, और ऑर्डर दूसरे देशों में चले गए. त्रञ्जऋ्छ की रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि सितंबर में स्थिति और भी खराब हो सकती है, क्योंकि यह पहला महीना होगा जब पूरे समय 50% का टैरिफ लागू रहेगा.

श्रम-प्रधान क्षेत्र जैसे परिधान, रत्न और आभूषण, चमड़े के उत्पाद, झींगा और कालीन, जिनमें अमेरिका की हिस्सेदारी 30% से 60% तक है, सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं.

उद्योग समूहों ने सरकार से त्वरित कार्रवाई की मांग की है. उनकी मांगों में ब्याज सब्सिडी, निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं के तहत तेजी से शुल्क वापसी, और वित्तीय सहायता शामिल है ताकि व्यापार बंद होने से रोका जा सके. सरकार ने हालांकि कुछ घरेलू उत्पादों पर त्रस्ञ में कटौती की है, लेकिन निर्यात-विशिष्ट राहत की घोषणा अभी तक नहीं हुई है.

तेल कीमतों की स्थिरता से बॉन्ड यील्ड में गिरावट संभव

नई दिल्ली, 17 सितंबर.एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, अनुकूल मुद्रास्फीति के आंकड़ों और तेल की कीमतों में स्थिरता के कारण अगले तीन महीनों में बेंचमार्क भारतीय बॉन्ड यील्ड में थोड़ी गिरावट आने की संभावना है.

यह गिरावट भारत की आर्थिक वृद्धि के लिए सकारात्मक संकेत है.रिसर्च फर्म क्रिसिल इंटेलिजेंस की रिपोर्ट बताती है कि 10-वर्षीय सरकारी बॉन्ड यील्ड, जो 31 अगस्त को 6.59 प्रतिशत थी, वह सितंबर के अंत तक 6.42 - 6.52 प्रतिशत और नवंबर के अंत तक 6.38 - 6.48 प्रतिशत के दायरे में आ सकती है. स्टेट डेवलपमेंट लोन यील्ड-नवंबर तक 7.23 प्रतिशत से घटकर 7.15 - 7.25 प्रतिशत के

दायरे में आ सकती है.

रिपोर्ट के अनुसार, कच्चे तेल की नरम कीमतें भू-राजनीतिक जोखिमों और वैश्विक आर्थिक मंदी के प्रभावों को कम कर रही हैं. बॉन्ड यील्ड को प्रभावित करने वाले अन्य प्रमुख कारक हैं-

- अमेरिकी फेडरल ओपन मार्केट कमेटी का आगामी निर्णय.
- अगस्त में घरेलू बाजार में 2.84 लाख करोड़ रुपये की बढ़ती तरलता.
- अमेरिका और भारत के बीच चल रही व्यापार वार्ताएं.

भारतीय शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन उछाल

नई दिल्ली, 17 सितंबर. द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अमेरिकी दल के साथ चल रही बातचीत की खबरों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के चलते भारतीय शेयर बाजार में बुधवार को लगातार दूसरे दिन तेजी दर्ज की गई. निवेशकों ने उत्साहपूर्वक आईटी, बैंकिंग और ऑटो शेयरों में जमकर खरीदारी की, जिससे बेंचमार्क सूचकांक नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए.30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स 313.02 अंक या 0.38 प्रतिशत की बढ़त के साथ 82,693.71 अंक पर बंद हुआ. कारोबार के दौरान यह 82,741.95 अंक के नए उच्चतम स्तर पर भी पहुंचा. इसी तरह, 50 शेयरों वाला एनएसई निफ्टी 91.15 अंक या 0.36 प्रतिशत की तेजी के साथ 25,330.25 पर बंद

उद्योगपतियों ने की पीएम मोदी की सराहना

मुकेश अंबानी ने कहा- मोदी को 100 साल पूरे होने तक देश की सेवा करनी चाहिए

नई दिल्ली, 17 सितंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन पर देश के प्रमुख उद्योगपतियों ने उनकी सराहना करते हुए उनके प्रयासों की तारीफ की. रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि प्रधानमंत्री को आजाद भारत के 100 वर्ष पूरे होने तक देश की सेवा करनी चाहिए.

अंबानी ने प्रधानमंत्री को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि यह संयोग नहीं है कि मोदी का अमृत महोत्सव भारत के अमृत काल में आ रहा है. उन्होंने आगे कहा, मेरी हार्दिक इच्छा है कि जब स्वतंत्र भारत 100 वर्ष का हो जाए, तब भी मोदी भारत की सेवा करते रहें.उन्होंने भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए किए जा

रहे प्रधानमंत्री के प्रयासों की सराहना की.

अन्य उद्योगपतियों की भी प्रशंसा- उदय कोटक- कोटक महिंद्रा बैंक के निदेशक उदय कोटक ने प्रधानमंत्री मोदी की सीखने और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भारत के लिए अपनाने की आदत की प्रशंसा की. उन्होंने कहा कि मोदी में दूरदर्शिता, क्रियान्वयन, जिज्ञासा और विनम्रता का अद्भुत मिश्रण है.

सुनील भारती मित्तल- भारती एंटरप्राइजेज के संस्थापक सुनील भारती मित्तल ने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी और प्रौद्योगिकी-प्रधान दृष्टिकोण की सराहना की. उन्होंने कहा कि इस दृष्टिकोण ने समावेशी प्रगति के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग की मजबूत नींव रखी है.

कुमार मंगलम बिड़ला- आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष कुमार मंगलम बिड़ला ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा अर्थव्यवस्था की स्थिति जानना चाहते हैं और निजी क्षेत्र को निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के तरीकों पर सवाल करते हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक बहुत ही उत्सुक श्रोता हैं, जो हर बात को ध्यानपूर्वक सुनते हैं.

मेकमाईट्रिप का जोमैटो के साथ साझेदारी

नयी दिल्ली 17 सितंबर (वार्ता) प्रमुख ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी मेकमाईट्रिप ने ट्रेन यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है. इसके तहत अब यात्री जोमैटो के 40,000 से अधिक रेस्टोरेंट पार्टनर से 130 से ज्यादा स्टेशनों पर अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकेंगे. यह सुविधा मेकमाईट्रिप ऐप पर ट्रेन टिकट बुक करने वाले यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी.

मेकमाईट्रिप ऐप से यात्री कर सकेंगे फूड ऑर्डर

नाश्ता, लंच, डिनर और स्नैक्स सब कुछ शामिल

मेकमाईट्रिप की फूड ऑन ट्रेन सेवा के माध्यम से नाश्ता, दोपहर का भोजन, रात का खाना और स्नैक्स उपलब्ध होंगे. कंपनी के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय रेलवे की ई-कैटरिंग सेवा का उपयोग

करने वाले यात्रियों की संख्या में 66% की वृद्धि हुई है, जो इस सेवा की बढ़ती मांग को दर्शाता है. यात्री अपनी यात्रा से सात दिन पहले तक पीएनआर का उपयोग करके सीधे अपनी सीट पर गरमागरम खाना मंगवा सकते हैं. मेकमाईट्रिप के मुख्य व्यवसाय अधिकारी (फ्लाइट्स, जीसीसी, कॉर्पोरेट ट्रैवेल) और मुख्य विपणन अधिकारी राज ऋषि सिंह ने कहा कि यह साझेदारी उनकी सेवाओं को और मजबूत करेगी.

ड्रोन परिचालन के लिए कानून

नियम तोड़ने पर तीन साल जेल और एक लाख जुर्माना

नई दिल्ली, 17 सितंबर ,बुधवार को, भारत सरकार देश में ड्रोन के उपयोग को विनियमित करने के लिए एक अलग कानून लाने की तैयारी में है. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने नागर ड्रोन विधेयक, 2025 का मसौदा जारी किया है.

इस विधेयक का उद्देश्य ड्रोन की खरीद-बिक्री, परिचालन, और नियमों के उल्लंघन पर सजा तथा जुर्माने के साथ-साथ तीसरे पक्ष के लिए बीमा और हर्जाने के नियमों को तय करना है.

विशिष्ट पहचान संख्या- मसौदा विधेयक के अनुसार, प्रत्येक ड्रोन के लिए एक अद्वितीय पहचान संख्या (यूआईएन) होना अनिवार्य होगा.

सुरक्षित क्षेत्र- केंद्र और राज्य सरकारों को किसी क्षेत्र को रेड जोन या येलो जोन घोषित करने का अधिकार होगा.

ताइवान की जीडीपी ने कोरिया को पीछे छोड़ा

TSMC की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी बढ़कर 70.2% हुई

एआई की तेज वृद्धि से सैमसंग फाउंड्री पीछे छूटी

ताइपे, 17 सितंबर, बुधवार को राष्ट्रीय विकास परिषद के प्रमुख येह चुन-ह्सियन ने ताइवान की प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में 2025 में दक्षिण कोरिया से आगे निकलने का श्रेय ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सफलता और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आई तेजी को दिया है.

फोकस ताइवान की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह 22 वर्षों में पहली बार होगा जब ताइवान इस मामले में दक्षिण कोरिया को पछाड़ेगा. कोरिया इकोनॉमिक डेली की रिपोर्ट के मुताबिक, ताइवान की प्रति व्यक्ति जीडीपी इस साल 38,066 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि दक्षिण कोरिया की यह 37,430 डॉलर रहेगी. येह ने कहा कि उन्होंने कई साल पहले ही इस प्रवृत्ति का अनुमान लगा लिया था. उन्होंने TSMC की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया, जिसने वैश्विक फाउंड्री व्यवसाय में अपनी बढ़त बनाई है, और यह बढ़त अगले 5-10 वर्षों तक जारी रहने की उम्मीद है.

सलाहकार फर्म ट्रेंडफोर्स कॉर्प की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, TSMC की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी इस साल की दूसरी तिमाही में बढ़कर 70.2% हो गई है.

समाचार विशेष

तो क्या टूट जाएगा आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन?

पटना. बिहार के चुनावी मैदान में एनडीए और इंडिया ब्लॉक के नेता सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मंथन करना शुरू कर चुके हैं. इस बीच शनिवार को मुजफ्फरपुर में आयोजित एक जनसभा में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया.

एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे. उनके इस बयान से गठबंधन की एकता पर सवाल उठने लगे हैं. अब इस बयान पर बिहार का सियासी पारा चढ़ गया है. शनिवार को मुजफ्फरपुर के कांटी में आयोजित एक जनसभा में तेजस्वी यादव ने कहा कि तेजस्वी बिहार की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगा. उन्होंने जनता से अपील की कि हर सीट पर तेजस्वी के चेहरे को देखकर वोट करें. इस बयान को गठबंधन सहयोगियों पर दबाव बनाने की कोशिश के रूप में भी देखा जा रहा है. तेजस्वी यादव ने सभा के दौरान नीतीश सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार के पास कोई विजन नहीं है और ये सिर्फ नकल करती है. साथ ही उन्होंने खुद को बिहार का भविष्य बताया और कहा कि राज्य को आगे ले जाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव उठाएगा.

सीट शेयरिंग को लेकर बढ़ती टेंशन- तेजस्वी यादव का यह बयान ऐसे समय आया है जब महागठबंधन के भीतर सीट बंटवारे को लेकर पहले से ही मतभेद हैं. झारखंड मुक्ति मोर्चा और लोक जनशक्ति पार्टी (पशुपति पारस गुट) के शामिल होने से मामला और जटिल हो गया है. सभी दल अपने-अपने हिस्से की सीटों को लेकर अड़े हैं, जिससे फॉर्मूला तय करना मुश्किल हो गया है. पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो आरजेडी ने 144 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 75 सीटें जीती थीं. वहीं कांग्रेस को 70 सीटें मिली थीं, जिसमें से उसने 19 पर जीत दर्ज की थी.

सहयोगी दलों के लिए असहज स्थिति

तेजस्वी यादव के इस बयान से यह सवाल उठने लगा है कि क्या आरजेडी-कांग्रेस गठबंधन में दरार आ सकती है. जहां एक ओर सीटों पर समझौता मुश्किल हो रहा है, वहीं दूसरी ओर इस तरह के बयान सहयोगी दलों के लिए असहज स्थिति पैदा कर रहे हैं. आने वाले हफ्तों में महागठबंधन के रुख से तस्वीर साफ होगी.

बड़ा दांव लगाने की तैयारी में गुर्जर

गुर्जर चौपाल के नाम से एक विशेष अभियान

लखनऊ. उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर अभी से राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हो गई हैं. इसी दौरान उत्तर प्रदेश की जाति व्यवस्था में भी एक अलग अलग जाति तथा अलग अलग समाज ने भविष्य की राजनीति की रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है.

इसी प्रकार की रणनीति उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज ने भी बड़ी तैयारी की है. उत्तर प्रदेश के गुर्जर समाज ने उत्तर प्रदेश में बड़ा राजनीतिक दांव खेलते हुए प्रदेश भर में एक विशेष अभियान शुरू किया है. गुर्जर समाज ने पूरे उत्तर प्रदेश में समाज को एकजुट करने तथा एक ही दिशा में राजनीतिक क़दम उठाने के लिए गुर्जर पाठशाला से लेकर विशाल गुर्जर महासभा तक का आयोजन करने की रणनीति बनायी है.

आपको बता दें कि गुर्जर समाज भारत का प्रसिद्ध समाज है. उत्तर प्रदेश से लेकर पूरी दुनिया में फैले हुए गुर्जर समाज का इतिहास बहुत ही गौरवशाली इतिहास है. इन दिनों उत्तर प्रदेश में गुर्जर चौपाल के नाम से एक विशेष प्रकार का अभियान चलाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में गुर्जर चौपाल के आयोजन का कारण बेहद खास कारण है. उत्तर प्रदेश के अलग-अलग जिलों में गुर्जर चौपाल के आयोजन के बाद एक विशाल गुर्जर सम्मेलन आयोजित करने की भी घोषणा की गई है. गुर्जर चौपाल का आयोजन करने के मुख्य सूत्रधार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी हैं.

ग्रेटर नोएडा में होगा गुर्जर समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी ने बताया कि गुर्जर राजनीतिक जागरूकता अभियान के तहत गुर्जर समाज का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. गुर्जर समाज के राष्ट्रीय सम्मेलन को विशाल गुर्जर जागरूकता रैली का नाम दिया गया है. विशाल गुर्जर जागरूकता रैली का आयोजन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में स्थित दादरी नगर में किया जाएगा. दादरी में होने वाली विशाल गुर्जर जागरूकता रैली के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होंगे. दादरी में होने वाली विशाल गुर्जर जागरूकता रैली नवंबर 2025 में आयोजित की जाएगी. इस रैली के आयोजन की तारीख की घोषणा जल्दी ही की जाएगी.

विधानसभा से पहले बीटीसी का चुनाव

गुवाहाटी. अगले साल अप्रैल में होने वाले असम विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों की तैयारियों और संभावनाओं की परीक्षा होने वाली है. अगले हफ्ते 22 सितंबर को बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद यानी बीटीसी का चुनाव होने वाला है.

बीटीसी की 40 सीटों के लिए मतदान होगा. इससे सिर्फ बोडोलैंड में पार्टियों की ताकत की परीक्षा नहीं होगा, बल्कि पूरे राज्य में परीक्षा होगी. ध्यान रहे यह बहुत अहम चुनाव होता है. पहले हागरामा महलारी की पार्टी बीपीएफ और भाजपा एक साथ थे. लेकिन बाद में भाजपा ने उनको छोड़ दिया और प्रमोद बोड़ो की पार्टी यूपीपीएल के साथ तालमेल कर लिया. इस समय बीटीसी में यूपीपीएल और भाजपा का बहुमत है. यूपीपीएल के 16 और भाजपा के 14 सदस्य हैं. महलारी की बीपीएफ के नौ सदस्य हैं और एक सदस्य हीरा सरानिया की पार्टी जीएसपी के पास है. कांग्रेस जीरो पर है. इस बार भी भाजपा और यूपीपीएल में अंदरखाने तालमेल है. भाजपा 30 सीटों पर, जबकि यूपीपीएल सभी 40 सीटों पर चुनाव लड़ रही है.

विशेष | **क्या बदलेगी प्रदेश की राजनीतिक तस्वीर**

सपा का पंचायत चुनाव से हटने का ऐलान

इटावा. उत्तर प्रदेश की राजनीतिक जमीन पर इस समय शिवपाल यादव चर्चा में है. शिवपाल यादव ने इटावा से जिस प्रकार पंचायत चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा की है, उसने तमाम राजनीतिक दलों के कान खड़े कर दिए हैं. शिवपाल यादव ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि समाजवादी पार्टी 2026 में होने वाले यूपी पंचायत चुनाव में हिस्सा नहीं लेगी.

पंचायत चुनाव में हिस्सा न लेने का फैसला आखिर में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को लेना है. हालांकि, शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के पद पर हैं. पार्टी में एक बड़ी जिम्मेदारी रखते हैं. ऐसे में उनके इस बड़े बयान को अखिलेश यादव की सहमति के बिना दिया जाना संभव नहीं दिखता है.

शिवपाल यादव के बयान ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी की रणनीति को एक प्रकार से साफ कर दिया है. अगर उनका बयान सही साबित होता है और चुनावी मैदान में समाजवादी पार्टी नहीं उतरती है तो इसका सीधा अर्थ बड़े अर्थ में देखा जा सकता है. दरअसल, उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव 2024 में समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक यानी पीडीए पॉलिटिक्स के जरिए भारतीय जनता पार्टी को मात देने में सफलता हासिल की.

हालांकि, समाजवादी पार्टी के जातीय गठजोड़ को यूपी उपचुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ने ध्वस्त कर दिया. लोकसभा चुनाव 2024 के बाद आगरा से बांग्लादेशी हिंदुओं के उत्पीड़न के मुद्दे को जिस प्रकार से सीएम योगी आदित्यनाथ ने छेड़ा. बंटोगे तो कटोगे का नारा दिया(उसने प्रदेश की राजनीति को एक अलग रुख दे दिया.

पर्दे के पीछे से खेल

समाजवादी पार्टी भले ही ऐलान कर रही हो कि वह पंचायत चुनाव के मैदान में नहीं उतरेगी, लेकिन उसके कार्यकर्ता चुनावी मैदान में दिख सकते हैं. सपा की ओर से बिना सिंबल लिए पार्टी का समर्थन हासिल कर पार्टी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे. वे भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते दिखेंगे. इसके जरिए समाजवादी पार्टी जमीन पर अपनी पकड़ को भी टोह लेगी. साथ ही, विपक्षी गठबंधन की एकता में भी सेंधमारी न हो, इसका भी ख्याल रखा जाएगा. अगर यूपी पंचायत चुनाव 2026 में समाजवादी पार्टी चुनावी मैदान में नहीं उतरती है तो कांग्रेस सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकती है.